पिटे मोहरे को फ़िर भाजपा की कमान

साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की रणनीति

अमितशाह को दोबारा भारतीय जनतापार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया है। यह लगभग तय माना जा रहा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भरोसा अमितशाह पर अभी भी बना हुआ है, जबकि बिहार में इनका चुनाव अभियान नाकामयाब रहा और भद्द भी काफ़ी पिटी। पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे वाला इनका जुमला भाजपा पर भारी पड़ गया। इसके बाद कई राज्यों में हुये निकाय चुनावों में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। साथ ही पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों को लेकर मोदी सरकार विरोधियों के निशाने पर हैं। हैदराबाद में दलित छात्र की आत्महत्या और इस पर बीजेपी संघ के नेताओं की प्रतिक्रियाओं से भी समाज का एक बड़ा वर्ग मोदी सरकार के खिलाफ़ होता जा रहा है। लेकिन संघ के पास मोदी और अमितशाह की जोड़ी के अलावा और कोई दूसरा मोहरा नहीं है। भूलना नहीं होगा कि मोदी और अमितशाह गुजरात के कुख्यात दंगों के मुख्य अर्किटेक्ट थे। इसके बाद भी गत लोकसभा चुनावों में साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की उनकी नीति सफ़ल रही। यद्यपि चुनाव प्रचार में पूंजीपतियों ने खुलकर इनकी मदद की, फ़िर भी संघ के लिये सबसे बड़ा औज़ार साम्प्रदायिकता ही है। संघ को विश्वास है कि आनेवाले दिनों में अमितशाह अपने जहरीले भाषणों और शाजिसों के सहारे चुनाव वैतरणी पार करने में भाजपा के लिये मददगार साबित होंगे। वैसे भी फ़िलहाल संघ एवं भाजपा के पास अमितशाह से अधिक शातिर अन्य कोई उपलब्ध भी नहीं है।

वैसे, भाजपा के अन्दर अमितशाह को दोबारा पार्टी का अध्यक्ष बनाये जाने पर कुछ असंतोष भी है, लेकिन वह दबा हुआ है। संघ ने भाजपा और सरकार ने नरेन्द्र मोदी की ऐसी ताना-शाही स्थापित कर दी है कि कोई भी किसी मुद्दे पर खुलकर बोलना नहीं चाहता। पहले भी संघ के निर्णय के विरुद्ध आवाज़ उठाने वालों का बुरा हश्र सामने आ चुका है। सबसे बड़े भुक्तभोगी तो लालकृष्ण आडवाणी रहे, जिन्हें पहले अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा और अब मार्गदर्शक मंडल में जिन्हें मूक रहने के लिये विवस कर दिया गया है।

अमितशाह को दोबारा पार्टी का अध्यक्ष बनाये जाने से यह साबित हो गया है कि आनेवाले दिनों में भाजपा एक बार फ़िर से देश में, खासकर उन राज्यों में दंगे भरकाने की नीति पर चल पड़ेगी जहां चुनाव होने हैं। इस वर्ष पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है और अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में। दोनों राज्यों में अमितशाह के नेतृत्व में संघ दंगे भरकाने की साजिश शुरू कर चुका है। दोनो राज्यों में फ़िलहाल जो सरकारें हैं, उनकी नीतियों के कारण संघ को सफलता मिलने की पूरी उम्मीद भी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने सिर्फ़ मुस्लिम की रैली बुलाई थी, जिसका परिणाम मालदा में हुए उपद्रव के रूप में सामने आ गया। अल्पसंख्यकों को एकजूट कर और उन्हें भड़काकर बहुसंख्यक साम्प्रदायिकता का जवाब नहीं दिया जा सकता, बल्कि इससे उसे और बढावा ही मिलेगा। वह और भी उग्र एवं आक्रामक होकर सामने आयेगा। ममता बनर्जी अगर इस बात को नहीं समझती तो अल्पसंख्यक ध्रुवीकरण से उन्हें फ़ायदा होने की जगह घाटा होगा और भाजपा की ताकत बढेगी, दूसरी तरफ़ उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही कमज़ोर सरकार बैठी हुई है। अखिलेस का अपना कोई वजूद नहीं है। मुलायम पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुके हैं। वोटरों को अपनी तरफ़ खींच पाने के लिये उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। रही-सही कसर जन्म दिन और सैफ़ई महोत्सव मनाकर पूरी कर देते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार उनका सफ़ाया होना तय है। मुलायम की इस कमज़ोरी से भाजपा का फ़ायदा उठाना भी तय है। यूपी में और कोई ऐसी दूसरी पार्टी नहीं दिखती जो अपने दम पर या किसी के साथ गठबन्धन कर सरकार बना सके। इसे देखते हुए भाजपा ने फ़िर से अयोध्या में राम मन्दिर निर्माण का राग अलापना शुरू कर दिया है। राम मन्दिर निर्माण के लिये राम शिलाएं जुटाने से लेकर तिथि तक कि घोषणाएं की जा रही है। भाजपा की साम्प्रदायिक चाल की काट किसी अन्य दल के पास नहीं है। बिहार में भाजपा की दाल इसलिए नहीं गल सकी कि वहां नीतिश कुमार और लालू यादव जैसे मजबूत वोट बैंक वाले नेता थे, जिनकी धर्मनिरपेक्ष छवि पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता। लेकिन मुलायम के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। मुलायम का जनाधार खत्म हो गया है अल्पसंख्यकों का विश्वास भी उनके प्रति नहीं रह गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश ही सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में सामने आ रहा है, जहां अगर भाजपा साम्प्रदायिक ध्रुविकरण में कामयाब हो गई तो यह देश की धर्मनिरपेक्ष ताकतों के लिये बहुत बड़ा झटका साबित होगा। जाहिर है, दूसरी बार भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद अमितशाह अपनी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश में ही झोंकेगे और गुजरात के बाद उसे हिन्दुत्व की दूसरी प्रयोगशाला बनाना चाहेंगे। ऐसा करने की कोशिश उन्होंने पहले भी की थी और अब तो और भी जोर-शोर से करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जीत से ही भाजपा को राज्यसभा में बहुमत मिल सकता है।

लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार की लगातार असफलताओं को देखते हुए इस बात में संदेह है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अमितशाह को किस हद तक कामयाबी मिल पायेगी। सिर्फ़ साम्प्रदायिक दंगे भरकाने की साजिश ही सफलता की गारंटी होती तो ऐसी कोशिश बिहार में भी इन्होंने कम नहीं की थी। राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार से जनता के बढते मोहभंग के कारण अमितशाह को चुनावी रणनीति बनाने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चुनावी वादों को जुमला कह कर अमितशाह पहले ही काफ़ी बदनाम हो चुके हैं और विश्वसनियता तो उनकी पहले भी कुछ नहीं थी। सिर्फ़ तिकड़म और साजिश ही उनकी ताकत रही है। अगर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजपार्टी और कांग्रेस का गठबन्धन सामने आता है तो यह भाजपा के लिये कड़ी चुनौती पेश करेगा। इससे अमितशाह को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अमितशाह रैलियों में भाषण देकर वोटरों को प्रभावित नहीं कर सकते। बन्द कमरे में बैठकर साजिश जितनी रच लें। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों का गठबंधन सामने आता है तो भी अमितशाह के लिये इसका मुकाबला करना कठिन होगा। अगर इन दो राज्यों में भाजपा को मनोवांछित सफ़लता नहीं मिलती है तो फ़िर संघ के सामने सवाल ये खड़ा होना कि 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिये भाजपा की कमान किसे दें। आखिर अमितशाह से बड़ा कोई दूसरा दंगाई संघ के पास है भी नहीं।

- मनोज

अगर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजपार्टी और कांग्रेस का गठबन्धन सामने आता है तो यह भाजपा के लिये कड़ी चुनौती पेश करेगा। इससे अमितशाह को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अमितशाह रैलियों में भाषण देकर वोटरों को प्रभावित नहीं कर सकते। बन्द कमरे में बैठकर साजिश जितनी रच लें। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों का गठबंधन सामने आता है तो भी अमितशाह के लिये इसका मुकाबला करना कठिन होगा। अगर इन दो राज्यों में भाजपा को मनोवांछित सफ़लता नहीं मिलती है तो फ़िर संघ के सामने सवाल ये खड़ा होना कि 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिये भाजपा की कमान किसे दें। आखिर अमितशाह से बड़ा कोई दूसरा दंगाई संघ के पास है भी नहीं।

तुर्की-ब-तुर्की / "जंगल ही कहां बचे जो जंगल राज की बात करते हो "बिहार में कानून का राज चलेगा।"

"बिहार में कानून का राज चलेगा।" (राज्य में जंगल राज पार्ट-II के आरोपों का सामना कर रही नीतीश सरकार के मुखिया ने यह दावा किया)

"हमारा कहना है-

नीतीश कुमार जी आपका दावा इस मामाले में सही लगता है कि बिहार से काटकर झाड़खंड राज्य बन जाने से सारा जंगल का इलाका नये राज्य में चला गया है। लिहाज़ा, जब जंगल ही नहीं है तो जंगल राज की बात करना भी बेमानी हो जाता है। जो बचे खुचे जंगल है भी उन्हें लालू यादव के ठेकेदारों द्वारा सफ़ाचर करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तब आपकी सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर या पटना के गांधी मैदान में विशाल जनसभा कर यह घोषणा कर सकती है कि राज्य में जंगल राज की संभावनायें पूरी तरह समाप्त हो गयी हैं।

वैसे, क्या ही अच्छा हो कि उन इन्जीनियरों, डॉक्टरों और व्यवसाइयों के घर वालों की भी इस मामले में क्या सोच है जान लिया जाय, जिनकी आपके शपथग्रहण के बाद फ़िरोती के लिये हत्या हुई हैं। उन्हें तो आपकी सरकार में परम सहयोगी लालू यादव की शक्ल सपने में देख कर भी डर लगता है। क्या आप उन्हें सपने देखना बन्द करा सकते हैं ?

यह तो सभी जानते हैं कि बिहार में भी कानून का शासन ही चलेगा। आखिर तो देश का संविधान व न्यायपालिका अपना काम देर सबेर कर ही रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह बनता है कि कानून के शासन को रोजमर्रा की जिंदगी में हांक कौन रहा है ? अगर हांकने की लाठी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके हाथ में है नीतीश जी तभी आपको ऐसा दावा करना चाहिये। आप भी जानते हैं कि आधी सरकार लालू यादव के साये तले है। क्या आप इस साये से बाहर आने की हिम्मत रखते हैं ? मोदी के भय से मुक्त हुआ मतदाता लालू के भय में वापस जाना नहीं चाहता। क्या लालू यादव यह विश्वास दिला पाने में कोई पहल करेंगे ?

लालू यादव अपनी चुटीली बातों से लोग़ों को हंसाने के लिये मशहूर हैं। कानून-व्यवस्था के मामले में उनकी भयानक चुप्पी लोग़ों को रोने पर मजबूर कर रही है। कहीं इस सरकार में आप मसखरा बन कर ही ना रह जायें नीतीश जी। राजनीति में न दो बादशाह हो सकते हैं और न दो जोकर। लालू जी पूर्ववत जोकर बने रहें इसके लिये जरूरी है कि आप एक मात्र बादशाह रहें। आपके महागठबंधन पर बिहार के लोगों का विश्वास तभी कायम रहेगा। अन्यथा वह कहावत तो आपने भी सुनी ही होगी कि काठ की हांडी बार-बार नहीं चढा करती।